

(b) if so, by what date and what industries would be encouraged therein?

The Minister of Commerce and Industry (Shri Lal Bahadur Shastri):

(a) Not yet, Sir

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यों के लिये राशि

४८३. { श्री खादीबाला :
श्री क० भ० मालवीय

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार का दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और उसमें से कितनी धनराशि अब तक व्यय हुई,

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि और क्यों व्ययगत हुई, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार व्ययगत राशि मध्य प्रदेश सरकार को देने का विचार कर रही है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र):

(क) से (ग) प्रश्न का आशय समस्त मध्य प्रदेश की योजना के लिए केन्द्र से मिलने वाली सहायता से है। राज्य सरकारों को केन्द्र से मिलने वाली धनराशि उनकी वार्षिक योजना के अनुसार प्रति वर्ष तय की जाती है। मध्य प्रदेश ने १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय सहायता के मद में क्रमशः १०६ करोड़ और १९७ करोड़ रुपये लिए थे और १९५८-५९ के लिए १८.५ करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई थी।

प्रादर्श ग्रामों के निर्माण की योजना

४८४. { श्री खादीबाला :
श्री क० भ० मालवीय }:

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रादर्श ग्राम निर्माण योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन को अब तक कितनी धनराशि दी गई है, और

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने प्रादर्श ग्राम बस गये हैं अथवा बसाये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चन्दा) (क) १९५७-५८ में मध्य प्रदेश सरकार के लिये ३७० लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी जिसका उस वर्ष वे उपयोग नहीं कर सके। १९५८-५९ में उस राज्य सरकार के लिये ५.२५ लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। केन्द्रीय सहायता देने की नई विधि के अनुसार राज्य सरकार की वार्षिक निर्धारित सहायता का तीन चौथाई भाग उस राज्य को कार्य चालू रखने के साधन के रूप में नौ मासिक किश्तों में पेशगी दे दिया जाता है और इसका हिसाब वर्ष के अन्त में दी गई स्वीकृतियों के अनुसार किया जायेगा। ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत चुने गये गांवों की मकान प्रयोजनाओं के लिये ये धनराशियां निर्धारित की गई हैं। इन चुने हुए गांवों में पर्याप्त मकान तथा दूसरी सुविधाएं मिल सकेंगी और इनसे आसपास के इलाकों को विकास के लिये प्रेरणा मिलेगी।

(ख) गत वर्ष राज्य सरकार को ३५ गांव अलाट किये गये थे और इस वर्ष ७० और गांव अलाट किये गये हैं। गांवों में मकान बनाने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने इन १०५ गांवों में से अभी तक ७८ गांव लिये हैं।